भारत सरकार
कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय
कृषि एवं किसान कल्याण विभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 1743
10 फरवरी 2026 को उत्तरार्थ

विषय: किसानों की आय बढ़ाने के लिए लागू की गई योजनाएं

1743. श्री रामवीर सिंह बिधूड़ीः

क्या **कृषि और किसान कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः
(क) सरकार द्वारा किसानों की आय बढ़ाने के लिए क्या प्रभावी उपाय किए गए हैं;
(ख) विगत दस वर्षों के दौरान सरकार द्वारा इस प्रयोजनार्थ कौन-कौन सी योजनाएं कार्यान्वित की गई हैं और तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और
(ग) इन योजनाओं के कार्यान्वयन के बाद किसानों की आय में कितनी वृद्धि हुई है?

उत्तर
कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री (श्री रामनाथ ठाकुर)

(क) से (ग): कृषि राज्य का विषय है, भारत सरकार उचित नीतिगत उपायों, बजटीय आवंटन और विभिन्न योजनाओं के माध्यम से राज्यों का समर्थन करती है। सरकार ने कृषि एवं किसान कल्याण विभाग (डीए एंड एफडब्ल्यू) के बजट आवंटन को 2013-14 के दौरान 21,933.50 करोड़ रुपये उल्लेखनीय बढ़ोतरी करते हुए वर्ष 2025-26 के बजट प्राक्कलन के दौरान 1,27,290.16 करोड़ रुपये कर दिया है। भारत सरकार ने किसानों की आय बढ़ाने और कृषि क्षेत्र के व्यापक विकास के लिए निम्नलिखित उपाय/रणनीतियाँ निर्धारित की हैं:-

(i) फसल उत्पादन/उत्पादकता बढ़ाना
(ii) उत्पादन लागत कम करना
(iii) किसानों की उपज से लाभकारी प्रतिफल प्राप्त करना ताकि उनकी आय में वृद्धि हो सके।
(iv) कृषि विविधीकरण
(v) फसल कटाई के बाद मूल्यवर्धन विकसित करना
(vi) सतत कृषि के लिए जलवायु परिवर्तन के साथ अनुकूलन और फसल हानि को कम करना

इन उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए सरकार द्वारा निम्नलिखित प्रमुख स्कीमें/कार्यक्रम कार्यान्वित किए जा रहे हैं;

1. प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (पीएम-किसान)
2. प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना (पीएम-केएमवाई)
3. प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान (पीएम-आशा)
4. प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (पीएमएफबीवाई)/ पुनर्संरचित मौसम आधारित फसल बीमा योजना (आरडब्ल्यूबीसीआईएस)
5. संशोधित ब्याज अनुदान योजना (एमआईएसएस)
6. एग्रीकल्चर इन्फ्रास्ट्रक्चर फंड (एआईएफ)
7. 10,000 नए किसान उत्पादक संगठनों (एफपीओ) का गठन और संवर्धन
8. राष्ट्रीय मधुमक्खी पालन और शहद मिशन (एनबीएचएम)
9. नमो ड्रोन दीदी
10. स्टार्ट-अप और ग्रामीण उद्यमों के लिए कृषि कोष (एग्रीश्योर)
11. राष्ट्रीय प्राकृतिक खेती मिशन (एनएमएनएफ)
12. राष्ट्रीय कृषि विकास योजना - विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (आरकेवीवाई-डीपीआर)
13. प्रति बूंद अधिक फसल (पीडीएमसी)
14. कृषि यंत्रीकरण उप-मिशन (एसएमएएम)
15. परम्परागत कृषि विकास योजना (पीकेवीवाई)
16. मृदा स्वास्थ्य एवं उर्वरता (एसएच एवं एफ)
17. वर्षा सिंचित क्षेत्र विकास (आरएडी)
18. कृषि वानिकी
19. फसल विविधीकरण कार्यक्रम (सीडीपी)
20. कृषि विस्तार उप-मिशन (एसएमएई)
21. राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा एवं पोषण मिशन (एनएफएसएनएम)
22. एकीकृत कृषि विपणन योजना (आईएसएएम)
23. समेकित बागवानी विकास मिशन (एमआईडीएच)
24. राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन (एनएमईओ) – ऑयल पाम
25. राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन (एनएमईओ) - तिलहन
26. पूर्वोत्तर क्षेत्र जैविक मूल्य श्रृंखला विकास मिशन
27. डिजिटल कृषि मिशन
28. राष्ट्रीय बांस मिशन
29. दलहन आत्मनिर्भरता मिशन
30. प्रधानमंत्री धन-धान्य कृषि योजना (पीएमडीडीकेवाई)

भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आईसीएआर) ने 75,000 किसानों की सफलता की कहानियों का संकलन जारी किया है, जिन्होंने कृषि एवं किसान कल्याण विभाग (डीए एंड एफडब्ल्यू) और संबद्ध मंत्रालयों/विभागों की स्कीमों के समन्वय से अपनी आय में दो गुना से अधिक वृद्धि की है।

राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण कार्यालय (एनएसएसओ), सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (एमओएसपीआई) ने राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण के 77वें चरण (जनवरी 2019 - दिसंबर 2019) के दौरान कृषि वर्ष जुलाई 2018 से जून 2019 के संदर्भ में देश के ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि परिवारों का स्थिति आकलन सर्वेक्षण (एसएएस) किया। इन सर्वेक्षणों के अनुसार, प्रति कृषि परिवार अनुमानित औसत मासिक आय वर्ष 2012-13 (राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण का 70वां चरण) में ₹6,426 से बढ़कर वर्ष 2018-19 (राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण का 77वां चरण) में ₹10,218 हो गई।

घरेलू उपभोग व्यय पर एनएसएसओ सर्वेक्षण (2023-24) के अनुसार, अखिल भारतीय औसत मासिक प्रति व्यक्ति उपभोग व्यय (एमपीसीई) के अनुमानों की तुलना निम्न प्रकार है:

क्षेत्र	विभिन्न अवधियों में औसत एमपीसीई (रु.)	
	2011-12 एनएसएस (68वां दौर)	2023-2024
ग्रामीण	1,430	4,122
शहरी	2,630	6,996
ग्रामीण एमपीसीई के प्रतिशत के रूप में अंतर	83.9	69.7

*****